साक्षरता को शिक्षा का पर्याय मानकर विकास की सुन्दर तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती रही है। माना गया कि साक्षरता दर में वृद्धि से सामाजिक समस्याओं से निजात मिलेगी। लेकिन हकीकत क्या है? यह लेख 2011 की जनगणना से प्राप्त साक्षरता के आंकड़ों को जेंडर समस्याओं से जोड़कर देखता है। यह बताता है कि साक्षरता दर की वृद्धि ने जेंडर समस्या को नया आयाम दिया है।

पढ़िए गीता बनिए सीता

(साक्षरता एवं जेंडर अनुपात के सह-संबंध)

प्रज्ञा जोशी

स्त्री सशक्तीकरण की प्रक्रिया में

शिक्षा की भूमिका प्रेरक, साधन और साध्य तीनों ही दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानी गई है। उसी तरह समाज के विकास में भी शिक्षा का अहम् स्थान है। समाज और देशों की भौतिक उन्नति में ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास में भी शिक्षा भूमिका निभाती है। हालांकि जब मानवीय चेहरे के विकास की बात उठ रही हो और विकास की संकल्पना कई प्रश्न चिह्नों से घिरी हो तो जाहिर है कि इस प्रश्न के कई सिरे सामने आएंगे। विकास के अनेक आयामों के साथ शिक्षा की प्रकृति, पद्धति और पहुंच ये सभी धागे उलझते नजर आएंगे। इस लेख में राजस्थान में महिला साक्षरता व बाल लिंगानुपात इन दो सिरों को गूंथकर कुछ सवाल उठाने का प्रयास किया गया है। इन दो पक्षों को आमने-सामने रखते हुए यह जानने का प्रयास है कि साक्षरता, जिसे शिक्षा का एक पक्ष माना जाता है, उसका समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति, जिसका एक सूचक बाल लिंगानुपात है, से किस प्रकार का संबंध है? वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े मार्च में प्रकाशित हुए, उन्हें आधार बनाते हुए पिछले दशक में इन संबंधों में आए परिवर्तन को इस लेख में प्रस्तुत किया जा रहा है। इन परिवर्तनों की व्याख्या करते हुए यह समझने की कोशिश की गई है कि शिक्षा और खासकर स्त्री शिक्षा जेंडर चेतना का समाज में संचार कर पाती है या वह पितृसत्तात्मक विकास के एजेंडा को संरचनात्मक स्तर पर लागू करने का एक जरिया बनकर रह जाती है।

विकास, शिक्षा और स्त्रियां : राष्ट्र-निर्माण और चेतना के स्वर

19वीं शताब्दी में भारत में जब स्त्रियों के लिए सार्वजनिक शिक्षा के द्वार खोल दिए गए तो ज्ञानोदय की रोशनी में वह राह राष्ट्रीयता, मध्यमवर्गीय और जातिगत चेतना के घुमावदार मोड़ों से

होकर गुजरती रही। यहां तक कि स्त्री के शिक्षित होने को राष्ट्र-निर्माण में शिक्षित और संस्कारित राष्ट्रवीरों की परवरिश करने के लिए माओं को शिक्षित करने की गरज के तौर पर देखा गया था। ऐसे में स्त्री चेतना या स्त्री मुक्ति के चिह्न शिक्षा में ढूंढ़ना मुश्किल ही था। फिर भी स्त्री शिक्षा से उठते चेतना के कई स्वर उस समय में भी देखे जा सकते हैं। जैसे-जैसे विकास में स्त्री शिक्षा का महत्त्व अधोरेखित किया जाने लगा वैसे-वैसे स्त्री शिक्षा की मुहिम सार्वजनीकरण की ओर बढ़ने लगी। स्त्रियां शिक्षा से रोजगार के क्षेत्र में आईं। यह इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था कि स्त्रियों का श्रम सार्वजनिक क्षेत्र में अवैतनिक नहीं रहा। शिक्षा ने स्त्रियों के लिए औपचारिक उद्योगों और ज्ञान के क्षेत्र में पैर जमाने के रास्ते बना दिए। विकास में स्त्रियों को दृश्यमान बनाने की कोशिश में हमने केवल शिक्षित स्त्रियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। पर सवाल आज भी कायम है कि क्या शिक्षा जेंडर संवेदनशील चेतना का विकास कर पाई है?

विकास को नापने के लिए जब पैमाने निर्धारित किए जा रहे थे तब मानव विकास सूचकांक 1990 में तैयार किया गया और उसके पांच साल बाद ही (1995) इसे जेंडर संबंधित विकास सूचकांक (GDI) तथा जेंडर सशक्तीकरण मानदंड (GEM) से जोड़ा गया ताकि मानवीय क्षमता और 'समृद्धि' का सर्वांगीण आलेख प्रस्तुत किया जा सके। जहां GDI स्त्री-पुरुषों के बीच जीवन-प्रत्याशा, आय और स्कूली नामांकन तथा वयस्क साक्षरता के आधार पर तुलना प्रस्तुत करता है वहीं GEM स्त्रियों की आर्थिक और राजनैतिक सहभागिता के पैमाने पर विकास को परखता है। यहां यह दर्ज करना जरूरी है कि इसी दौरान बीजिंग सम्मेलन में सभी देशों ने महिला सशक्तीकरण की वकालत करते हुए महिलाओं की सहभागिता और निर्णय क्षमता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया था और उसके लिए शिक्षा की प्रेरक भूमिका को चिह्नित किया था (सक्सेना, साधना 1995)। यह परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन था। विकास में महिलाएं (WIDWomen in Development) और महिला और विकास (WADWomen and Development) इन दो परिप्रेक्ष्यों से हटकर यह परिप्रेक्ष्य जेंडर आधारित मुद्दों को विकास के विमर्श में मुख्यधारा में लाने के संदर्भ में दृढ़ था। इसी दौर में आशियाई देशों में एक तरफ 'कार्य' की परिभाषा में परिवर्तन लाकर महिलाओं के श्रम को मुख्यधारा में दृश्यमान करने के प्रयास हो रहे थे और दूसरी तरफ औद्योगीकीकरण और आर्थिक उदारीकरण की तेज और व्यापक प्रक्रियाओं के बरक्स वहां बाल लिंगानुपात का पौरुषीकरण बढ़ता जा रहा था। जनसंख्या से 'गुमशुदा लड़कियां' एक आशियाई परिघटना के रूप में सामने आई। अमर्त्य सेन कहते हैं कि जब सामान्यतः सभी समान परिस्थितियां रखने पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है तो गिरता हुआ बाल लिंगानुपात और वहां से झांकती '100 मिलियन गुमशुदा लड़कियां' विकास के अलग ही आयाम पेश कर देती हैं (सेन, अमर्त्य 1990)। ऐसे में आशियाई समाजों में आर्थिक (अ) विकास के चलते क्षमतावर्धन ही नहीं बल्कि जिंदा रहने के अवसर लड़कियों के हिस्से में असमान आते हों वहां शिक्षा की उपलब्धता और अनुपलब्धता उनके अस्तित्व, प्रस्थिति और चेतना पर कैसे प्रभाव डाल रही है, इसकी पड़ताल जरूरी हो जाती है।

विकास की राजनीति की पार्श्वभूमि में आशियाई देशों में विकास के केन्द्र (Centre) और परिधि (Periphary) के प्रदेशों में इन प्रभावों की तीव्रता तथा बुनावट अलग होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया से 10 करोड़ बच्चियां गायब हैं, उसमें से एशिया से गायब 6 करोड़ लड़कियों में से 3.05 करोड़ चीन से, भारत से 2.28 करोड़, पाकिस्तान से 31 लाख, बांग्लादेश से 16 लाख और नेपाल से 2 लाख लड़कियां गायब हैं। अगर इन देशों के 2011 के मानव विकास सूचकांक

लेखक परिचय

महिला अध्ययन विभाग, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर में समाजशास्त्र का अध्यापन कर रही हैं।

के आंकड़े (अनुक्रम से 0.687, 0.547, 0.504, 0.500, और 0.458) देखें तो यह बात चीन के अपवाद को छोड़कर उभरकर आती है कि कैसे विकास और जेंडर प्रस्थिति में नकारात्मक सह-संबंध है। इस लेख में राजस्थान की चर्चा इसी दृष्टिकोण से की जा रही है। मानव विकास के आधार पर राजस्थान मध्यम स्तर के सबसे निचले पायदान पर 0.537 अंकों के साथ 35 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में 28वें स्थान पर है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 43,641.2 रुपये है और आय सूचकांक 0.640 है। वहीं शिक्षा का सूचकांक 0.755 तो स्वास्थ्य संबंधी 0.735 है। इन सभी दृष्टि से राजस्थान को प्रसिद्ध जनांकिकीविद् आशीष बोस ने 'बीमारू' राज्यों की श्रेणी में रखा था। अब इन राज्यों को थोड़ा परिष्कृत संबोधन दिया गया है : 'एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप' (EAG)[1]। संबोधन बदलने से परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आता। उसके लिए जरूरत होती है नजरिया बदलने की और उसके आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित करने की। इस समय जब राजस्थान की पाठ्यचर्या बन रही है तब यह पड़ताल और भी सामयिक बन जाती है कि शिक्षा और जेंडर सूचकांक में कैसा परस्पर संबंध है?

2011 की जनगणना : भारत के संदर्भ में कुछ तथ्य

भारत में 2011 की जनगणना में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 1951-61 के बाद सबसे कम (17.64) रही है। परन्तु 2001 की जनगणना में साक्षरता दर में आए उछाल को बरकरार रखने में हम असफल रहे हैं। साक्षरता में जेंडर अंतराल की निरंतर कमी आई है। दूसरी तरफ भले ही पिछले दो दशकों से स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार से कुल जनसंख्या के लिंगानुपात में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है[2], परन्तु 1961 से लगातार बाल लिंगानुपात गिर रहा है। होना तो यह चाहिए था कि साक्षरता में जेंडर अंतराल कम होने के साथ समाज में जेंडर आधारित अन्य असमानताएं कम होनी चाहिए थी। परन्तु 2011 की जनगणना के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। हालांकि यह चित्र केवल राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत के संदर्भ में लागू होता है।

इन दोनों मानदंडों के संदर्भ में विषयान्तर का खतरा उठाते हुए यह बात जोड़ देना चाहूंगी कि जनगणना की मुख्य तालिकाएं जब प्रकाशित हुईं तो पहली बार जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता और लिंगानुपात के साथ बाल लिंगानुपात के आंकड़े एक साथ प्रस्तुत किए गए। यह अनायास ही नहीं था। दरअसल शासन साक्षरता में हुई प्रगति को उजागर करने के लिए यह चाहता था कि साक्षरता दर में 7 वर्ष आयु की जनसंख्या की साक्षरता दर को प्रधानता से दिखाया जाए। ऐसे में 0-6 उम्र की जनसंख्या और उनके अनुपात को प्रस्तुत करना आवश्यक था, इसलिए प्राथमिक तालिका में सामने आया बाल लिंगानुपात का गिरता ग्राफ। निचली तालिका में यह बात स्पष्ट है कि 1981-91 के दशक में बाल लिंगानुपात में 17 बिंदुओं की गिरावट दर्ज हुई थी और लिंगानुपात में 7 बिंदुओं की। इसी समय साक्षरता दर में हो रही वृद्धि की रफ्तार कम हुई थी (1961 से लेकर 2011 तक साक्षरता दर में दशकीय परिवर्तन अनुक्रम से इस प्रकार है : 6.15, 9.12, 8.64, 12.62 और 10.81) इसलिए साक्षरता कार्यक्रमों को 1991 के बाद प्राथमिकता दी गई थी ताकि साक्षरता दर को बढ़ाया जा सके। स्वाभाविक है कि सरकार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई उन्नति को दर्ज करना पहली प्राथमिकता थी। चूंकि लिंगानुपात में वृद्धि थी तो इसका अर्थ था कि स्त्रियों की मृत्यु दर जिसमें सबसे अधिक हिस्सा मातृत्व मृत्यु का होता है, उसे कम करने में भी शासन सफल रहा है। जनसंख्या की वृद्धि दर को घटाने में भी सफलता पाई गई है। परन्तु शासन 1991 में बाल लिंगानुपात में आई भारी गिरावट के प्रति उदासीन था[3]। ऐसे में शासकीय नीतियों और योजनाओं से हासिल हुई विकास और उन्नति की राह पर गुमशुदा हुई लड़कियां खामोशी में ही दर्ज कर गईं अपने गुमशुदा होने की रिपोर्ट।

1. EAG राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये सात राज्य शामिल हैं।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.6 से बढ़कर 2011 में 65.4 हो गई है। साथ ही यह भी दर्ज करना होगा जब भारत में मातृत्व मृत्यु दर (301-2006) में कमी आई है। चिकित्सा सेवाओं का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में वृद्धि के कारण यह संभव हुआ है जिसका सीधा प्रभाव लिंगानुपात में निरंतर दो दशकों में आई वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है।

3. भारत सरकार के योजना आयोग के द्वारा प्रकाशित 11वी योजना के दस्तावेजों में जब लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे थे तो स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों में कहीं भी गिरते हुए बाल लिंगानुपात से संबंधित लक्ष्य नहीं हैं कि लिंगानुपात बढ़ाना है, मातृत्व मृत्यु दर में कमी लानी है। गिरते बाल लिंगानुपात को बढ़ाने का लक्ष्य आता है महिला और बाल विकास के मुद्दों में। साफ है कि इसे सरकार स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न नहीं मानती और चूंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल आशियाई समस्या के रूप में देखा जा रहा है तो सरकार पर विकास संबंधित लक्ष्य निर्धारित करने में साक्षरता दर बढ़ाना, लिंगानुपात बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि कम करना, मातृत्व मृत्यु दर कम करना इन मुद्दों पर जैसा अंतर्राष्ट्रीय दबाव है वैसा दबाव इस प्रश्न पर नहीं है।

तालिका 1 : भारत में साक्षरता दर व जनसंख्या के जेंडर अनुपात तथा उनके दशकीय परिवर्तन।

वर्ष	साक्षरता दर		साक्षरता दर में दशकीय परिवर्तन		जेंडर अंतराल (Gender Gap)	लिंगानुपात	लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन	बाल लिंगानुपात (0-6)	बाल लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री					
1951	27.16	08.86	--	--	18.30	946	01	--	--
1961	40.4	15.35	13.24	06.49	25.05	941	-05	976	--
1971	45.96	21.97	05.56	06.62	23.98	930	-11	964	-08
1981	56.38	29.76	10.42	08.79	26.62	934	04	962	-02
1991	64.13	39.29	07.75	09.53	24.84	927	-07	945	-17
2001	75.26	53.67	11.13	14.38	21.59	933	06	927	-18
2011	82.14	65.46	06.88	11.79	16.68	940	07	914	-13

1. 1951, 1961 और 1971 में साक्षरता दर पांच साल और उससे ज्यादा उम्र की जनसंख्या का है जबकि 1981, 1991, 2001 और 2011 की जनगणना में सात साल और उससे अधिक उम्र की जनसंख्या के आधार पर नापी गई है।
2. 1981 की साक्षरता दर में असम की साक्षरता दर शामिल नहीं है। 1991 की जनगणना में जम्मू-कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं।
3. ---- आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जनसांख्यिकी और शिक्षाविदों ने पुरजोर ढंग से सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा कि 2001 की जनगणना के आधार पर गिरता हुआ बाल लिंगानुपात शिक्षित वर्ग में दिखने वाली परिघटना है। यही कारण है कि जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बनाई गई तो शिक्षा के माध्यम से जेंडर संवेदनशीलता निर्माण करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि शिक्षा नीति में पिछले तीन दशकों से जेंडर समानता लाने के लक्ष्य को रखे जाने के बावजूद शिक्षा की पहुंच अभी भी जेंडर असमानता बरकरार रखे हुए है। दूसरी तरफ पाठ्यचर्या से जेंडर के मुद्दे नदारद हैं और यह भ्रान्ति बना दी गई है कि जेंडर के मुद्दे यानी महिलाओं के मुद्दे हैं, पूरे समाज के मुद्दे नहीं (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2006)। जिस तरह यह मान लिया जाता है कि असमान लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात केवल महिलाओं का प्रश्न है, पूरे समाज या देश के विकास से इसका ताल्लुक नहीं है। अगला सेक्शन इस भ्रान्ति को दूर करने का एक प्रयास है। शिक्षा, विकास और समता आधारित तथा हिंसा मुक्त समाज यह परस्पर गुंथे हुए प्रश्न हैं। खासकर उन समाजों में ये प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं, जहां सामंती संरचना के अंदर असमान विकास की एकरेखीय सोच शिक्षा को शोषण, दमन और हिंसक मूल्यों को समाज में पनपाने का जरिया बन जाती है।

राजस्थान 2011 जनगणना : जेंडर संरचना

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 1901 (905) के बाद सबसे अधिक रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई प्रवृत्ति का प्रतिबिंब राजस्थान की जनगणना के लिंगानुपात में भी दिखता है, पिछले दो दशकों से लिंगानुपात बढ़ा है। पर राष्ट्रीय औसत से 14 अंक नीचे राजस्थान (926) EAG राज्यों में बिहार (916) और उत्तर प्रदेश (908) के बाद तीसरे स्थान पर है। इस जनगणना में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात का अंतर भारत और राजस्थान दोनों में ही 21 अंकों से घटा है। परन्तु इस वृद्धि के बावजूद यह बात दर्ज करनी होगी कि पिछली जनगणना में दो जिले- डूंगरपुर और राजसमन्द में लिंगानुपात 1000 से अधिक था परन्तु इस दशक में किसी भी जिले का लिंगानुपात 1000 के आंकड़े को छू नहीं पाया। यहां तक कि राष्ट्रीय प्रवृत्ति के विपरीत डूंगरपुर, जालौर, राजसमन्द, उदयपुर, चूरू, सीकर और सिरोही इन 7 जिलों में लिंगानुपात में गिरावट आई है। चिंता की बात यह है कि इनमें से अधिकतर वे जिले हैं जो अपने ज्यादा लिंगानुपात के लिए जाने जाते रहे हैं और यह गिरावट मामूली अंकों की नहीं है। जैसे डूंगरपुर, जो पिछली जनगणना में लिंगानुपात में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है वहां 32 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। इसका अर्थ है कि इन जिलों में विकास के असमान प्रतिरूपों के चलते हुए पलायन, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की अनियमित पहुंच और उपलब्धता के परिणामस्वरूप लिंगानुपात गिरा है। इन जिलों में से सीकर और चूरू को छोड़ बाकी पांच जिलों में स्वास्थ्य सूचकांक न्यूनतम दर्जे का रहा है जिसमें डूंगरपुर का सूचकांक 0.282 तो दूसरी तरफ जालौर का 0.497 रहा है (आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय तथा विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर 2008)।

तालिका 2 : राजस्थान बाल लिंगानुपात और महिला साक्षरता दर : दशकीय परिवर्तन

जिले का नाम	बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष की उम्र के बच्चों के संदर्भ में)						बाल लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन	महिला साक्षरता दर						महिला साक्षरता दर में दशकीय परिवर्तन
	2001			2011			2001-11	2001			2011			2001-11
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
राजस्थान	909	914	934	883	886	869	-26	43.85	37.33	64.67	52.66	46.25	71.53	8.81
गंगानगर	850	861	814	854	859	841	.4	52.44	47.19	67.81	60.07	55.65	71.78	7.63
हनुमानगढ़	872	876	854	869	875	845	-3	49.56	46.27	62.57	56.91	53.48	70.76	7.35
बीकानेर	916	921	917	902	902	901	-14	42.45	30.27	64.76	53.77	44.81	70.12	11.31
चूरू	911	910	898	896	897	893	-15	54.36	52.37	59.14	54.25	51.13	62.00	-0.11
झुंझुनू	863	865	852	831	825	852	-32	59.51	59.25	60.53	61.15	59.86	65.54	1.64
अलवर	887	894	837	861	864	844	-26	43.30	38.56	70.35	56.78	52.69	75.22	13.48
भरतपुर	879	882	864	863	867	840	-16	43.56	39.06	60.95	54.63	50.85	69.43	11.07
धौलपुर	860	863	839	854	858	837	-6	41.84	38.89	54.19	55.45	53.23	63.51	13.67
करौली	873	871	890	844	842	855	-29	44.43	42.81	53.78	49.18	47.05	60.79	04.75
स.माधोपुर	902	901	906	865	866	862	-37	35.17	29.52	58.45	47.8	42.65	67.80	12.63
दौसा	906	908	880	859	861	842	-47	42.25	39.95	61.58	52.33	49.85	69.14	10.08
जयपुर	899	911	884	859	865	852	-40	55.52	43.86	67.13	64.63	52.07	75.82	09.11
सीकर	885	882	898	841	836	860	-44	56.11	55.27	59.34	58.76	56.75	65.26	02.65
नागौर	915	916	913	888	886	894	-27	39.67	36.85	53.41	48.63	45.92	60.03	08.96
जोधपुर	920	926	902	890	889	895	-30	38.64	24.75	64.34	52.57	41.99	71.85	13.93
जैसलमेर	869	870	860	868	868	871	-1	32.05	27.26	58.10	40.23	36.06	66.81	08.18
बाडमेर	919	920	896	899	900	891	-20	43.45	42.04	60.22	41.03	38.92	67.45	-02.42
जालौर	921	922	910	891	891	888	-30	27.80	26.18	47.80	38.73	37.03	57.32	10.93
सिरोही	918	931	847	890	895	859	-29	37.15	31.29	64.12	40.12	33.02	67.41	02.97
पाली	925	927	914	895	899	876	-30	36.48	31.65	54.65	48.35	43.74	64.55	11.87
अजमेर	922	930	906	893	898	883	-29	48.90	32.66	72.15	56.42	41.87	77.48	07.52
टोंक	927	929	920	882	882	887	-45	32.15	25.66	56.03	46.01	40.14	65.54	13.86
बूंदी	912	916	888	886	886	887	-26	37.79	32.46	60.04	47.00	41.56	68.16	9.21
भीलवाड़ा	949	959	903	916	921	894	-33	33.43	26.16	61.97	47.93	41.08	73.40	14.5
राजसमन्द	936	939	911	891	893	880	-45	37.68	33.10	68.29	48.44	43.77	72.95	10.76
डूंगरपुर	955	959	877	916	919	850	-39	31.77	28.86	67.82	46.98	44.75	78.29	15.21
बांसवाड़ा	964	967	868	925	928	863	-39	29.22	25.05	76.59	43.47	40.47	80.28	14.25
चित्तौड़गढ़	929	930	904	903	907	881	-26	35.99	28.95	68.87	46.98	40.68	74.80	10.99
कोटा	912	922	901	889	899	881	-23	60. 43	49.85	69.39	66.32	54.23	74.28	05.79
बारां	919	921	910	902	906	887	-17	41.56	37.66	60.33	52.48	48.24	68.25	10.92
झालावाड़	934	941	885	905	909	888	-29	40.02	35.25	68.16	47.06	42.01	72.84	07.04
उदयपुर	948	957	879	920	927	872	-28	44.49	36.26	77.49	49.10	40.46	82.02	04.61

राजस्थान में बाल लिंगानुपात 1981 के बाद 71 अंक गिरकर 883 पर आया है। न्यूनता की तरफ बाल लिंगानुपात जाने की प्रवृत्ति राजस्थान के कई जिलों में फैल चुकी है। 2001 की जनगणना में केवल गंगानगर, धौलपुर और हनुमानगढ़ ये तीन जिले थे जिनका बाल लिंगानुपात न्यूनतम श्रेणी यानी 862 से नीचे था जबकि 2011 की जनगणना में 10 जिले इस श्रेणी में आ चुके हैं। राज्य के औसत के आधार पर विभाजन देखें तो 2001 की जनगणना में उस समय के 32 जिलों में से 23 जिले राज्य के औसत से अधिक बाल लिंगानुपात रखते थे और 2011 में केवल 9 जिले राज्य के औसत से ऊपर की रेखा को छू पा रहे हैं (देखें तालिका : 2)।

2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में अंतर्राज्यीय स्तर पर बाल लिंगानुपात के संदर्भ में निम्न प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं :

- राजस्थान के आदिवासी अंचल के सभी जिले जिनमें वैसे तो उच्चतम बाल लिंगानुपात का स्तर दिखता है पर इन सभी जिलों में बाल लिंगानुपात में पिछले दशक में खासी गिरावट हुई है। देश के अन्य आदिवासी इलाकों में भी यह प्रवृत्ति इस जनगणना में उभरकर आई है।

- दूसरी तरफ 2001 की जनगणना में जिन जिलों में बाल लिंगानुपात का न्यूनतम स्तर था वहां गिरावट में तेजी की प्रक्रिया कम हुई है। यहां तक कि गंगानगर में बाल लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है हालांकि उसके बावजूद वहां बाल लिंगानुपात का स्तर काफी कम है।

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जिन तीन जिलों में सबसे कम है : गंगानगर (10.06), झुंझुनू (11.81) और पाली (11.99) बाल लिंगानुपात के स्तर पर न्यूनतम श्रेणी में आते हैं। यानी हमारी जनसंख्या नियंत्रण के लिए हो रहे परिवार नियोजन हमारे बाल लिंगानुपात को असंतुलित कर रहा है।

- पिछली जनगणना में शहरी क्षत्रों में बाल लिंगानुपात अधिक गिरा था परन्तु इस जनगणना में यह प्रवृत्ति ग्रामीण इलाकों में अपने पैर पसार रही है। हालांकि राज्य स्तर पर देखें तो शहरी क्षेत्र में 65 अंकों की गिरावट है तो ग्रामीण क्षेत्र में 28 अंक। ग्रामीण क्षेत्र में 30 अंकों से अधिक गिरावट बाल लिंगानुपात में दर्ज करने वाले जिलों की संख्या 20 है जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसे जिलों की संख्या केवल 8 है। गंगानगर में तो शहरी क्षेत्र में 27 अंकों की बढ़ोतरी है। सिरोही (12), जैसलमेर (11) और अलवर (09) जिलों के भी शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात में बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

- वे जिले जिनमें साक्षरता की दर ज्यादा है वहां बाल लिंगानुपात तेजी से गिर रहा है जैसे जयपुर, झुंझुनू, और सीकर। दूसरी तरफ वे जिले हैं, जहां साक्षरता की दर कम है और बाल लिंगानुपात अधिकतम है जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पर ध्यान लेने लायक बात यह है कि इस दशक में जिन जिलों में महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि पाई गई है वहां बाल लिंगानुपात तेजी से गिर रहा है जैसे डूंगरपुर (15.21) और बांसवाड़ा (14.25)।

- मानव विकास सूचकांक जिन जिलों में सर्वाधिक रहा है वहां बाल लिंगानुपात का स्तर न्यूनतम रहा है जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और अलवर। यह ध्यान देने लायक है कि ये जिले पारंपरिक रूप से असंतुलित लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात के लिए कुप्रसिद्ध जिले नहीं हैं जैसे जैसलमेर, धौलपुर, भरतपुर, करौली या सवाई माधोपुर- जहां लिंगानुपात कभी 900 के आंकड़े को पार नहीं कर पाता हो। ये वे जिले हैं जहां आर्थिक सूचकांक, साक्षरता का सूचकांक और स्वास्थ्य सूचकांक उच्च स्तरीय रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि ज्यों समृद्धि और शिक्षित मध्यम वर्ग का इन जिलों में विस्तार हुआ है बाल लिंगानुपात का स्तर गिर गया है।

साक्षरता दर के संबंध में 2011 की जनगणना में राजस्थान का परिवेश

साक्षरता दर के संदर्भ में राजस्थान ने पिछले पचास सालों में काफी प्रगति हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर की तरह यहां भी 1991-2001 के दशक में जो प्रगति हासिल की गई वह अभूतपूर्व थी। परन्तु इस दशक में निरक्षरता को मिटाने के संदर्भ में राज्य का सर्वाधिक नकारात्मक योगदान (-3.41) रहा है। पुरुषों की साक्षरता दर के संदर्भ में राजस्थान का स्थान देश के 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 27वां है परन्तु जैसे ही महिला साक्षरता दर की बात आती है, राजस्थान सबसे निचले स्थान पर खड़ा मिलता है। यह संयोग नहीं है कि 2001 में बाल लिंगानुपात के संदर्भ में देश में सबसे निम्न श्रेणी में आठवें स्थान को प्राप्त करने वाला यह राज्य 2011 में 26 अंकों की गिरावट के साथ पांचवें स्थान पर आ जाता है। हरियाणा, पंजाब, जैसे राज्य और चंडीगढ़, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश भले ही बाल लिंगानुपात में न्यूनतम स्तर पर हो लेकिन पिछले दशक में उन्होंने अपने स्तर को सुधारा है। जबकि राजस्थान में यह स्तर और भी नीचे गिरा है। जैसे ही जेंडर

असमानता की बात आती है वैसे ही राजस्थान का विकास का भ्रम काफूर हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का जेंडर अंतराल (Gender Gap) पिछले दशक में 4.15 से कम हुआ वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह अंतराल कम (3.58) होने की प्रक्रिया अभी भी थोड़ी धीमी है। यही वजह है कि इन दोनों क्षेत्रों में साक्षरता वृद्धि के जेंडर अनुपात पर होने वाले परिणाम अलग-अलग दिखाई देते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में जहां झुंझुनू, सीकर और कोटा साक्षरता दर के मामले में क्रमशः शीर्ष स्थानों पर हैं वहीं शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर में राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र ने बढ़त ली है। इस श्रेणी में क्रमशः उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर शीर्षस्थ हैं। यह थोड़ा उलझन पैदा करता है क्योंकि शिक्षा को शहरी से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ विस्तार के रूप में आमतौर पर देखा जाता है तो जिन क्षेत्रों में ग्रामीण इलाके साक्षरता में उन्नत्ति कर रहे हों वहां के शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर फैलाव उतनी तेजी से क्यों नहीं रह पाता? और कैसे फिर इन्हीं ग्रामीण सुशिक्षित क्षेत्र में बाल लिंगानुपात घटता है? कैसे कम बाल लिंगानुपात के लिए कुख्यात जिलों के साथ डूंगरपुर के शहरी क्षेत्र का बाल लिंगानुपात न्यूनता की श्रेणी में जा बैठता है? यहां पर शिक्षा के समता और चेतना लाने के उद्देश्यों पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी समाजों में प्रकृति के सह-अस्तित्व पर टिकी न्यूनतम जीवन निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था में सरलतम श्रम विभाजन के चलते विषमतामूलक जेंडर संबंध कम पाए जाते हैं और यही कारण है कि जिन जिलों में आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्य है, वहां लिंगानुपात तथा बाल लिंगानुपात में असंतुलन कम पाया जाता है। परन्तु इन क्षत्रों में साक्षरता प्रसार के साथ ही जब गिरते बाल लिंगानुपात के साक्ष्य मिलते हैं तो लगता है कि या तो आदिवासी समाज में जेंडर समतामूलकता के मूल्य होना एक मिथक है अथवा हमारी शिक्षा में जेंडर विषमता फैलाने वाले तत्व कूट-कूटकर भरे हैं, जिन्होंने आदिवासी मूल्य व्यवस्था का ह्रास किया है।

शहरी क्षेत्र में साक्षरता और खासकर महिला साक्षरता में न्यूनतम परिवर्तन दिखता है। इसके तीन कारण हैं- एक तो यहां पहले ही साक्षरता दर का स्तर ऊंचा है तो इसके फैलाव की गुंजाइश कम है और इसका अर्थ है कि साक्षरता का सार्वजनीकरण हमेशा ही एक दिवास्वप्न रहने वाला है। दूसरा यह कि नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण शहरों का फैलाव ग्रामीण क्षेत्र में जिस तेजी से हो रहा है उतनी तेजी से नगरीय मूल्य व्यवस्था (urbanism) का फैलाव नहीं हो रहा है या फिर यूं कहें कि नगरीकरण आजीविका का केंद्र बनता हुआ हमेशा पलायन को बढ़ावा देता है और यह पलायन करने वाले समूह कि निरक्षरता शहरी क्षेत्र के साक्षरता दर को नीचे खींचती है। पर ये तीनों ही कारण कुल मिलाकर विकास, आजीविका और साक्षरता के बीच सह-संबधों पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं।

साक्षरता बराबर विकास और आधुनीकरण का संरचनावाद से प्रेरित सिद्धांत तब चित्त हो जाता है जब साक्षरता के जरिए विषमता और सामंती पितृसत्तात्मक मूल्य अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं या विकास का पहिया उल्टा घूमने लगता है। झुंझुनू, सीकर और जयपुर इन जिलों में बाल लिंगानुपात की गिरावट का सिलसिला पिछले दो दशकों से निरंतर रूप से चला आ रहा है और इसका प्रभाव इस दशक में सामने आ रहा है। अब यहां जनसंख्या से लड़कियां केवल गायब ही नहीं हो रही हैं अपितु शिक्षा से भी महरूम होती जा रही हैं। झुंझुनू और सीकर के ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता दर पिछले दशक में मात्र 0.61 और 1.48 बढ़ी है। फिर से याद कर लें, ये दोनों ही वे जिले हैं जहां शिक्षा सूचकांक काफी ऊंचा यानी क्रमशः 0.850 और 0.837 रहा है (डीईएस और आईडीएस, 2008)। 1991 में इन जिलों की ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता दर अनुक्रम में 22.00 और 15.47 तो 2001 में यही दर अनुक्रम में 59.25 तथा 55.27 रही है। इसका अर्थ है कि जब 2001 में इन जिलों के बाल लिंगानुपात में भारी गिरावट आने का चलन शुरू हुआ तभी ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि आई पर 2011 में यह रफ्तार ही लगभग रुक गई। जब कि झुंझुनू में शहरी क्षेत्र में जहां बाल लिंगानुपात में कोई गिरावट नहीं हुई वहीं महिला साक्षरता की दर में पांच अंक की वृद्धि दर्ज हुई। यही चित्र बाड़मेर और सिरोही में दिखता है जहां 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात के गिरने के साथ महिला साक्षरता दर में गिरावट आई या वृद्धि न्यूनतम थी परन्तु शहरी क्षेत्र में जहां बाल लिंगानुपात में गिरावट का अनुपात तुलनात्मक दृष्टि से कम था वहां उसी अनुपात में महिला साक्षरता में वृद्धि पाई गई है।

यह साक्ष्य किसी भी सामान्यीकरण और निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए नाकाफी है, यह मानते हुए भी इन तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती। वे भविष्य में संभावित प्रवृत्तियों की ओर इशारा कर रहे हैं। राजस्थान मानव विकास रिपोर्ट बताती है कि जिन जिलों में मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है वहां पर भी अधिकतम 35 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। हमारे विकास की दृष्टि में ये प्राथमिकताएं नहीं हैं। मूलभूत सुविधाओं में इतनी विषमता रखकर हम कैसे साक्षरता को पा सकते हैं और ऐसी पाई साक्षरता स्वाभाविक ही समतामूलक खासकर जेंडर समतामूलक चेतना का विकास नहीं कर पाएगी।

मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शिक्षा की विषयवस्तु की पड़ताल होना आवश्यक है। स्कूली शिक्षा और अधिकाधिक रूप से उच्च शिक्षा जेंडर विषमताओं को पाटने में नाकामयाब रही है। पूर्वाग्रह के आरोप लगने के खतरे को उठाते हुए भी यहां कहना होगा कि हमारी शिक्षा तकनीक के ऐसे प्रयोग का प्रसार करने का माध्यम बनती जा रही है जिसमें लड़कियां जन्म से पूर्व लिंगाधारित गर्भपात से इसलिए खत्म की जाती हैं क्योंकि उनका जन्मना परिवार के लिए घाटे का सौदा है। जब परिवार नियोजन एक जीवन मूल्य की तरह प्रचारित हो रहा है वहां लिंगाधारित नियोजन एक सामान्य भाव बनता जा रहा है। दूसरे बच्चे के जन्म के संदर्भ में पारिस्थितिक बाल लिंगानुपात के एक अध्ययन अनुसार जब पहला बच्चा लड़की थी तो बाल लिंगानुपात में खासी गिरावट दर्ज की गई। सर्वाधिक चिंता का विषय यह था कि यह गिरावट उन माताओं के संदर्भ में कहीं अधिक थी जिन्होंने 10 या उससे अधिक साल तक शिक्षा पाई थी, बनिस्बत उन माताओं के जो निरक्षर थीं और इसी तर्ज पर यह गिरावट गरीब परिवारों की अपेक्षा समृद्ध परिवारों में कहीं अधिक थी। जबकि अगर पहला बच्चा लड़का था तो दूसरे बच्चे के समय किसी भी लिंग परीक्षण की भी आवश्यकता परिवार महसूस नहीं करते थे और न ही किसी प्रकार की उल्लेखनीय गिरावट बाल लिंगानुपात में देखी गई (झा, 2011)।

ऐसे में सिरे से विचार करना होगा कि विकास की दिशा क्या है और उसमें शिक्षा की भूमिका क्या रहेगी? जेंडर समता व न्याय के बिना न शिक्षा अपनी सार्थक भूमिका निभा पाएगी और न ही विकास अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। जेंडर आधारित मुद्दों को महिला के प्रश्न के रूप में विमर्श की दहलीज के बाहर करके और एक झरोखे से उन्हें केवल झांकने की अनुमति देकर प्रतीकात्मक उपस्थिति से न ही इन समस्यों का हल निकलेगा और न ही विकास का रथ आगे जा पाएगा। हमें राज्य के स्तर पर इसे प्राथमिकता देनी होगी कि जेंडर न्याय व समता के मूल्यों को पाठ्यचर्या और शिक्षा की आधारभूत संरचना में कैसे शामिल किया जाए ताकि जेंडर संवेदनशीलता एक जीवन शैली के रूप में समाज के हर एक तबके में पनपे। साक्षरता शिक्षा का एक चरण है वैसे ही प्री कन्सेप्शन प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट (PCPNDT Act) को सख्ती से लागू करना गिरते बाल लिंगानुपात के असंतुलन को कम करने की तरफ एक कदम भर है। राजस्थान के समाज में जहां संरचनात्मक रूप से इन कुप्रथाओं की जड़ें गहरी हों वहां शिक्षा और विकास के अन्य घटकों को अपनी जिम्मेवारी उठानी होगी। समाज में स्त्रियों के लिए अगर सम्मान होगा, समान अवसर होंगे, समान मूल्य होंगे, हिंसा रहित जीवन होगा तभी विकास और सशक्तीकरण की संभावनाएं अपना आकाश और जमीन पा सकेंगी। ◆

संदर्भ सूची

1. डी.ई.एस. और विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर, (2008) 'राजस्थान मानव विकास रिपोर्ट' http://statistics-rajasthaan-gov-in (15.07.2011 को देखा गया)।
2. चंद्रमौली, सी. (2011) 'पेपर 2: रूरल-अर्बन डिस्ट्रिब्युशन ऑफ पोपुलेशन' सेंसस 2011 http://www-censusindia-gov-in (17.07.11 को देखा गया)।
3. झा, प्रभात एवं अन्य (2011) 'ट्रेंड्स इन सिलेक्टिव्ह अबोर्शंस ऑफ गर्ल्स इन इंडियाः अनालिसीस ऑफ नैशनली रीप्रेसेंटेटीव्ह बर्थ हिस्टरीज् फ्रॉम 1990 टू 2005 एंड सेंसस डाटा फ्रॉम 1991 टू 2011', दी लैंसेट, खंड 377, अंक 9781, पृ. 1921-1928 http://www-thelancet-com/journals (15.07.2011 को देखा गया)।
4. बोस, आशीष (2007) 'इंडियाज् अन्बोर्न डोटर्स - व्हिक्टिम्स ऑफ डेमोग्राफिक टेर्रोरीसम', एक बीज वक्तव्य प्रपत्र जिसे 'जेंडर इश्यूज एंड एम्पोवार्मेंट ऑफ वीमेन' इस विषय पर कोलकाता में आयोजित एक सेमीनार में प्रस्तुत किया गया।
5. भारत सरकार (2011) 'प्रोव्हीजनल पोप्यूलेशन टोटल्स पेपर 1 'जनगणना 2011, http//www-censusindia-gov-in/2011&prov_results_ paper1_india-html (01.04.2011 को देखा गया)।
6. सक्सेना, साधना (1995) 'एज्युकेशन एंड वीमेन ऑन दी बीजिंग एजेंडा', इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, नवम्बर 25।
7. सेन, अमर्त्य (1990) 'मोर देन 100 मिलियन वीमेन आर मिसिंग', न्यूयॉर्क रीव्यू ऑफ बुक्स, 37 (20)।
8. यू.एन.डी.पी. (2011) 'ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2011', http://hdr-undp-org/en/media/HDR_2011_EN_Tables-pdf (20.01.12 को देखा गया)।